आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 01.12.2025 समय : 1905

- संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा – सत्र केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है।
- देशभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सी बी आई करेगी।
- दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने एक आदेश जारी कर मकान मालिकों और प्रबंधकों को किरायेदारों और घरेलू नौकरों का विवरण स्थानीय पुलिस को देने का निर्देश दिया है।
- अंडमान निकोबार के खिलाड़ियों ने भोपाल में आयोजित आठवीं अंतर–राज्य चैलेन्ज़र रोइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।

<><><><><><><>

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में उन्नीस दिनों की अवधि में कुल पन्द्रह बैठकें होंगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर बारह बजे जब कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क – संशोधन विधेयक दो हजार पच्चीस पेश किया। श्रीमती सीतारामन ने पान मसाला जैसी विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर लगाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक दो हजार पच्चीस भी पेश किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र केवल एक परम्परा ही नहीं बल्कि भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है।

<><><><><><><>

देशभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सी बी आई करेगी। यह जांच अन्य किसी स्कैम से अलग और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सी बी आई को मामलों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। साथ ही एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बैंकरों की भूमिका की जांच करने की पूरी आजादी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इंटरपोल की मदद भी ले सकती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फर्जी या एक ही पहचान पर कई सिम कार्ड जारी करने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत प्रस्ताव दाखिल करे। इसका उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों को सख्त दिशानिर्देश जारी करना है ताकि सिम कार्ड का दुरुपयोग रोका जा सके और अपराधियों पर लगाम कसी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें तुरंत साइबर क्राइम सेंटर स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि आईटी एक्ट 2021 के तहत दर्ज हर एफआईआर को सीबीआई को सौंप दिया जाए ताकि एक केंद्रीकृत और मजबूत जांच हो सके।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया चार नवम्बर से शुरू कर दी है। इस प्रयास का उद्देश्य सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और सूची की सटीकता सुनिश्चित करना है। श्री विजयपुरम तहसील के बूथ लेवल अधिकारी किरण, मनीष कुजूर, बीना दास रॉय, सुशांत सील और असीम भट्टाचार्य ने अपने–अपने क्षेत्रों में नामांकन पत्रों का सौ प्रतिशत वितरण और संग्रह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी कमलेश्वर राव ने इन अधिकारियों की सराहना करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट अर्जुन शर्मा ने एक आदेश जारी कर मकान मालिकों और प्रबंधकों को अपने आवासीय तथा व्यवसायिक संपतियों को किराए पर देने से पहले किरायेदारों, पेइंग गेस्ट और घरेलू नौकरों का विवरण स्थानीय पुलिस को देने का निर्देश दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दो हजार तेईस की धारा एक सौ तिरसठ के तहत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य असामाजिक तत्वों को शांति भंग करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकना है। यह आदेश कल से प्रभावी होगा और साठ दिनों तक लागू रहेगा। जिन्होंने घरेलू नौकरों की सूचना अब तक पुलिस को नहीं दी

है, उन्हें भी इस दौरान जानकारी देना अनिर्वाय होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दो हजार तेईस की धारा दो सौ आठ के तहत सख्त कारवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

प्रशासन के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में इस वर्ष पन्द्रह दिसम्बर से अगले वर्ष दस जनवरी तक आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यह निर्णय अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई उच्चस्तरीय आगंतुको की पूर्व सूचना के कारण लिया गया है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार के खिलाड़ियों ने भोपाल में आयोजित आठवीं अंतर–राज्य चैलेन्ज़र रोइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर द्वीप समूह का नाम रोशन किया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षु स्नेहा टोप्पो और पी अलगम्माल ने महिला कोक्सलेस पेयर इवेन्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीस नवम्बर को हुए फाइनल में कांस्य पदक अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता छब्बीस से तीस नवम्बर तक मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित अपर लेक पर आयोजित की गई थी।

<><><><><><><>

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली सुबह सात बजे नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल पहुंचकर समपन्न हुई। इसमें स्कूल और कॉलेज के करीब छह सौ विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ प्रशासन की स्वास्थ्य सचिव ऋचा द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. सूजा एंटनी और अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एच आई वी और एड्स के प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम और उपचार में प्रगति को उजागर करना और रोग से जुड़े भेदभाव का मुकाबला करना है। इस वर्ष का विषय है– व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन। इस सिलसिले में द्वीप समूह में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिनमें समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं और किशोरो की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

<><><><><><><>

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी दो हजार छब्बीस सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यह पुनः पंजीकरण सभी ओपन और डिस्टेन्ट लर्निंग तथा ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए लागू है। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि पन्द्रह जनवरी दो हजार छब्बीस है। जनवरी दो

हजार पच्चीस के वार्षिक सत्र और जुलाई दो हजार पच्चीस के सेमीस्टर सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र पुनः पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही की जा सकती है।

<><><><><><><><>